

## भारत में विकासात्मक समूह

# भारत में विकासात्मक समूह

### स्वयं सहायता समूह (SHG)

- ⊕ समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
  - ⊕ सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
  - ⊕ SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- ⊕ नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- ⊕ भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- ⊕ **सफलता की कहानियाँ:**
  - ⊕ वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
  - ⊕ केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

### सहकारी समितियाँ

- ⊕ जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
  - ⊕ सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- ⊕ **विनियमन अधिनियम:**
  - ⊕ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
  - ⊕ राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- ⊕ **97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
  - ⊕ सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
  - ⊕ अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - ⊕ भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- ⊕ **उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

### गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- ⊕ पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- ⊕ **पंजीकृत:**
  - ⊕ **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
  - ⊕ **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
  - ⊕ **कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- ⊕ **संवैधानिक प्रावधान:**
  - ⊕ **अनुच्छेद 19(1)(c)**- संघ बनाने का अधिकार
  - ⊕ **अनुच्छेद 43**- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - ⊕ **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

**FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।**

### प्रमुख NGO:

- ⊕ **NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
- ⊕ **अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

**NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।**



**Drishti IAS**

और पढ़ें: [SHG के माध्यम से महिला-सशक्तीकरण पर SBI का अध्ययन](#), [NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करना](#), [भारत का सहकारी क्षेत्र](#) ।

